RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

सीएम ने वितरित की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किट।
पेज 3

वर्षः 01 | अंकः 15 देहरादून, शुक्रवार 24 जुलाई 2026 | मूल्य 2 रुपये | पृष्ठः 8 | www.aawamindia.com

नीट पेपर लीक विवाद

कैबिनेट बैठक में होंगे सख्त फैसले: पीएम

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलनरत छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए और कड़े कदम उठाएगी, इसके लिए आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सख्त फैसले लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अब तक कई कार्रवाई की जा चुकी हैं और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना और उनकी शैक्षणिक प्रक्रिया प्रभावित न होने देना है।

गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिवावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वैध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है। वह जेल में पड़े हैं।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा हो जाए। इसका प्रबंध किया जाए। और अभी पांच-छह दिन पहले रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है।

उन्होंने ये भी कहा कि हम वहां संतोष मानने वालों में से नहीं हैं। इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के मसौदा पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरु हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

सोनम वांगचुक का टूटा अनशन, क्या कमजोर होगा आंदोलन

नई दिल्ली: केंद्रिय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह की अगुवाई में सरकार सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने में कामयाब हो गयी है। देर रात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रिय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह मेंदाता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक को मनाकर उनका अनशन तुड़वा दिया। सोनम वांगचुका का ये अनशन 26 दिन चला और सीजेपी के आंदोलन को धार देने में अहम भूमिका निभाने वाला रहा। उनके आंदोलन के 20 दिन सरकार ने उन्हें धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती किया था। अब उनके अनशन टूटने के बाद आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि पेपर लीक आंदोलन में विपक्ष के चक्रव्यूह में सेंध लगाने की रणनीति गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में तैयार हुई है जिसमें उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे।

अनशन तोड़ने से पहले केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो से सम्पर्क साधा था। सरकार ने उन्हें अपने स्तर पर भरोसा दिलाया और उनके माध्यम से सोनम को मनाने का प्रयास किया जो कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि सरकार वांगचुक की अधिकांश मांगों पर सहमत है और परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव होंगे। इससे वांगचुक अनशन तोड़ने पर राजी हो गए। हालांकि सोनम और आंदोलनकारियों की पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।

सोनम वांगुचक ने अनशन तोड़ने के बाद अपना वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि केंद्रिय मंत्री यहां आये थे, उनसे पहले एपेक्स बॉडी के लोग और लगभग 65 सांसदों ने हस्ताक्षर देकर अनशन तोड़ने के लिए कहा था और अब सरकार ने लिखकर आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि आंदोलन में भाग ले रहे बच्चों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। दूसरा पेपर लीक हादसे में मृत बच्चों को उचित मुआवजा दिया जायेगा। तीसरा परीक्षाओं में जवाबदेही लाने के मामले में संसद में बहस होगी और सख्त कानून लाये जायेंगे।

धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार उन्हें कोई आश्वसन नहीं दे पा रही थी पर मेरे सामने दो रास्ते थे कि मैं आगे अनशन करता और यूं ही खत्म हो जाता या फिर आपके मुताबिक ही जैसा कि कहा जाता है कि आपकी जान कीमती है। सोनम ने कहा कि यदि धमेंद्र इस्तीफा नहीं देते है तो इससे हानि बच्चों को ना होकर खुद सरकार होगी। धर्मेंद्र यदि इस्तीफा दे देते तो सरकार का नुकसान बच जाता।

सोनम वांगचुक का टूटा अनशन, क्या कमजोर होगा आंदोलन

नई दिल्ली: केंद्रिय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह की अगुवाई में सरकार सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने में कामयाब हो गयी है। देर रात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रिय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह मेंदाता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक को मनाकर उनका अनशन तुड़वा दिया। सोनम वांगचुका का ये अनशन 26 दिन चला और सीजेपी के आंदोलन को धार देने में अहम भूमिका निभाने वाला रहा।

शेष पृष्ठ तीन पर

आंदोलन में राहुल के कूदने से बदल गया माहौल

राहुल गांधी और उनके सहयोगी विपक्ष के नीट पेपर लीक आंदोलन में कूदने से आंदोलन का रूख ही बदल गया है। 20

जुलाई तक सोनम वांगचुक और सीजेपी के अभीजीत दिपके तक सीमित आंदोलन ने अब अलग रूख इख्तियार कर लिया है। एक ओर जहां संसद में विपक्षी पार्टी धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोरदार तरीके अड़ी हुई है तो सड़क पर भी विपक्ष अलग ही अंदाज में दिखायी दे रहा है। एक दिन विपक्षी सांसदो के साथ प्रधानमंत्री आवास का अचानक घेराव और दूसरे दिन बस में बैठकर गांधी स्मृति जाने ने सरकार को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया।

शेष पृष्ठ तीन पर

आगामी कावड़ से सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी देहात शेखर सुयाल ने थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक

रुड़की। कांवड़ यात्रा को सकुशल, व्यवस्थित व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने नगर निगम सभागार में जनपद के सात थानों के थाना प्रभारी निरीक्षकों,उपनिरीक्षकों व एसपीओ की बैठक आयोजित की,जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं,सुझावों तथा एसपीओ की ड्यूटी संबंधित कार्यप्रणाली को लेकर दिशानिर्देश दिए गए।एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि रुड़की क्षेत्र के लिए कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,क्योंकि पांच करोड़ कांवड़ यात्रियों में से लगभग चार करोड़ यात्री रुड़की से ही होकर गुजरते हैं,जिनमें सबसे अधिक दिल्ली,हरियाणा, मेरठ,मुजफ्फरनगर और राजस्थान के होते हैं,बाकी पंजाब व हिमाचल के कम संख्या में आते हैं,जिनका डाइवर्जन रुड़की से ही होता है,जो बहुत संवेदनशील और सतर्कता बरतने योग्य होता है।शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि एसपीओ साहिबान को पुलिस के साथ जो सेवा की जिम्मेदारी दी जाती है,वो बखूबी निभाते हैं,परंतु ये भी शिकायत मिली है कि पांच प्रतिशत एसपीओ केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कार्ड का प्रयोग करते हैं,जिसपर इस बार विशेष ध्यान दिया जाएगा।एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि रुड़की,मंगलौर,भगवानपुर,कलियर,झबरेड़ा के सीओ प्रत्येक सेवा पॉइंट पर समय-समय पर निरीक्षण कर निगरानी करेंगे।उन्होंने कहा कि नगर व आसपास के नागरिकों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की जाएगी कि कांवड़ यात्रा के दौरान नगर क्षेत्रों में फोर व्हीलर का प्रयोग कम से कम किया जाए,ताकि नगर की जनता को परेशानी न हो।सीओ रुड़की ओशिन जोशी,सीओ भगवानपुर सुमित पांडेय,सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी,अंतरराष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी,वरिष्ठ समाजसेवी ईश्वर लाल शास्त्री,थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप बिष्ट,थाना प्रभारी गंग नहर मणिभूषण श्रीवास्तव,एसएसआई धर्मेंद्र राठी,पार्षद डॉ०नवनीत शर्मा ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर कलियर,मंगलौर व भगवानपुर मार्गों पर पानी,बिजली और टैंट आदि की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने पर बल दिया।उत्तराखंड उर्दू अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष व अंतरराष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा रुड़की और आसपास के लोगों के लिए धार्मिक यात्रा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की जीती जागती मिसाल है,जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी अन्य धर्मों के लोगों के साथ मिलकर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और उनको पानी व फल वितरित कर उसी प्रकार सौहार्द का संदेश देते हैं,जिस तरह ईद पर हिन्दू भाई मुस्लिमों को ईदगाह पर मिठाई खिलाकर कर शुभकामनाएं देते हैं।ये रुड़की की पुरानी परंपरा है।सीओ रूडकी व सीओ मंगलौर ने कहा कि विशेष रूप से सभी ये ख्याल रखें कि अफवाहों पर ध्यान न देकर ध ैर्य,शालीनता के साथ कानून और नियमों के अनुरूप अपने सेवा कार्यों को जारी रखना है।बैठक में सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट के लिए नगर निगम की ओर से कार्यालय अधीक्षक अब्दुल कय्यूम ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।एसआई भगवानपुर रमेश कुमार सैनी,एसआई मंगलौर देवेन्द्र सिंह,एसआई मनोज कुमार,विपिन कुमार,सलमान फरीदी,प्रेमा नन्द प्रेमा,अमित वर्मा ,राजीव शास्त्री,मुस्तफा त्यागी, अंकित सैनी,रेनू अग्रवाल,ताहिर अली,शिवम गोयल पार्षद,मयंक गौतम,परमजीत सिंह,अबदुस समद,सत्यम सैनी सहित धनारी, कलियर मंगलौर,झबरेड़ा,भगवानपुर,नगला,रहमतपुर, सालियर,बढेड़ी,लंढौरा व रामपुर आदि के एसपीओ ने भाग लिया।बैठक का संचालन देशबंधु गुप्ता ने किया।

पिरान कलियर में 758वें सालाना उर्स 2026 की तैयारियां शुरू, 13 अगस्त से होगा उर्स का आयोजन

हरिद्वार । जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुध वार को जिला कार्यालय सभागार में 758वें सालाना उर्स/मेला-2026 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधि कारियों को उर्स मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 758वां सालाना उर्स 13/14 अगस्त 2026 से 03/04 सितम्बर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। चाँद दिखाई देने पर मेहंदी डोरी की रस्म के साथ उर्स का शुभारम्भ होगा। वहीं मुख्य आयोजन 24 अगस्त से 28 अगस्त तक संपन्न होंगे।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उर्स प्रारम्भ होने से पूर्व मेला क्षेत्र से सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से समय सीमा में कार्य पूर्ण करें ताकि देश-विदेश से आने वाले जायरीनों को कोई परेशानी न हो।

इन व्यवस्थाओं पर हुई खास चर्चा

बैठक में अस्थायी कार्यालय, चौकियां, जर्मन हैंगर, बैरिकेडिंग, दुकानें, विद्युत, मोबाइल शौचालय, पार्किंग, सफाई, पेयजल, चिकित्सा, अग्निशमन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्यों की ई-निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।पुलिस विभाग को सुरक्षा, अस्थायी चौकियां, भीड़ नियंत्रण, जल पुलिस और मोटर बोट तैनात करने के निर्देश दिए गए। रेलवे/परिवहन विभाग अतिरिक्त ट्रेनें, शटल बसें चलाएगा। नगर पंचायत साफ-सफाई, जल संस्थान पेयजल, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर-एम्बुलेंस और अग्निशमन विभाग संसाध न उपलब्ध कराएगा।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि उर्स के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि सभी विभाग समन्वय से काम कर समय पर व्यवस्थाएं पूरी करें।बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ, विधायक पिरान कलियर फुरकान अहमद, नगर मजिस्ट्रेट हर गिरि, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, त्ज्ब् कृष्ण चंद्र पलारिया, उप नगर आयुक्त अमरजीत कौर, तहसीलदार विकास अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

भारत ने डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का पक्षकार बनते हुए अपना स्वीकृति पत्र जमा किया

नई दिल्ली। भारत ने डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते (एएफएस) की स्वीकृति का दस्तावेज जमा कर दिया, जिससे वह इस समझौते का एक पक्ष बन गया। स्वीकृति का दस्तावेज भारत सरकार के वाणिज्य सचिव की ओर से डब्ल्यूटीओ महानिदेशक को औपचारिक तौर पर सौंपा गया। भारत का यह निर्णय तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा, आजीविका और रोजगार के स्रोत के रूप में समुद्री संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ संपोषित मत्स्य प्रबंधन के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। जून 2022 में जेनेवा में आयोजित 12वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, पर्यावरणीय संपोषण के उद्देश्य से बनाया गया पहला बहुपक्षीय डब्ल्यूटीओ समझौता है। यह अवैध मछलियां पकड़ने की गतिविधियों और मछली भंडारों के अत्यधिक दोहन के लिए सरकारी सहयोग पर रोक लगाता है, जिससे समुद्री जीवन की सुरक्षा में योगदान मिलता है।

डब्ल्यूटीओ के दो-तिहाई सदस्यों की ओर से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद यह समझौता 15 सितंबर 2025 को लागू हुआ। भारत डब्ल्यूटीओ का 123वां सदस्य है, जिसने अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया है। यह समझौता समुद्री वन्य मछलियां पकड़ने और समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़ी गतिविधियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जलीय कृषि और अंतर्देशीय मत्स्य पालन इस समझौते के दायरे से बाहर हैं। यह समझौता संपोषित मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देकर पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों की आजीविका की रक्षा करता है। यह अवैध, अनधिकृत और अनियमित (आईयूयू) मछलियां पकड़ने और बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी गई मछलियां के भंडारण में मछली पकड़ने से जुड़ी सब्सिडी पर रोक लगाता है, जिससे समुद्री संसाधनों को खतरे में डालने वाली मछलियां पकड़ने की अस्थिर प्रथाओं का समाधान होता है और पारंपरिक व छोटे पैमाने के मछली पकड़ने वाले समुदायों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा होती है। यह दूर-दराज के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले देशों की ओर से संचालित बड़े, भारी सब्सिडी वाले औद्योगिक मछली पकड़ने वाले बेड़ों का सहयोग करने वाली हानिकारक सब्सिडी पर लगाम लगाकर एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक मत्स्य पालन व्यवस्था भी बनाता है। इससे भारत जैसे देशों को लाभ होता है, जहां मत्स्य पालन मुख्य तौर पर छोटे पैमाने पर होता है और जो औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने में प्रमुख भागीदार नहीं हैं।

यह समझौता एक जिम्मेदार समुद्री खाद्य निर्यातक के तौर पर भारत की विश्वसनीयता को और बेहतर करता है, जिससे उन प्रीमियम बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है जो स्थिरता और पता लगाने की क्षमता को अधिक महत्व देते हैं। साथ ही, भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में मत्स्य पालन आधारित झींगा मछली की प्रधानता, जो समझौते के दायरे से बाहर है, देश के समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र की निरंतर मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करती है। भारत में एक सुदृढ़ मत्स्य प्रबंधन फ्रेमवर्क है, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के संपोषित दोहन संबंधी नियम, 2025 और भारतीय ध्वज वाले मत्स्य जहाजों की ओर से खुले समुद्र में मत्स्य पालन के संपोषित दोहन संबंधी दिशानिर्देश, 2025 के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया गया है। ये तरीके, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और अन्य मत्स्य प्रबंधन, निगरानी और संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रही क्षमता निर्माण पहलों के साथ मिलकर, समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। ये नियामक, संस्थागत और विकासात्मक फ्रेमवर्क भारत को समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ पारंपरिक और लघु-स्तरीय मछुआरों के लिए नीतिगत गुंजाइश बनाए रखने में सक्षम बनाता है। मत्स्य पालन सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समझौता समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और संपोषित इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ विकासशील और सबसे कम विकसित सदस्य देशों के लिए उचित तन्यकशीलता प्रदान करने का प्रयास करता है। भारत की ओर से इस समझौते को स्वीकार करना संपोषित मत्स्य प्रबंधन और भरोसेमंद समुद्री संसाधन शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का घरेलू मत्स्य प्रबंधन फ्रेमवर्क समझौते के अनुरूप है और यह पारंपरिक और लघु मछुआरों के हितों की रक्षा करते हुए संपोषित मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस समझौते का पक्षकार बनकर भारत डब्ल्यूटीओ को केंद्र में रखते हुए नियम-आधारित व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 02 मेडिकल मोबाइल वैन का फ्लैग ऑफ

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने श्रमिक और श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 02 मेडिकल मोबाइल वैन का भी फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिक कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज शुरु की जा रही कल्याणकारी योजनाएं भी श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री पोषण योजना" के माध्यम से जहां श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं ष्मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजनाष के माध्यम से श्रमिक भाई -बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर शुरू की जा रही ष्मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रमष के जरिए श्रमिक परिवारों में हाइजीन किट का वितरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही, ष्मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजनाष के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत हर साल 210 बच्चों को आवासीय सुविधायुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ष्मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजनाष के अंतर्गत शुरू की जा रही मोबाइल मेडिकल वैंस के जरिए विशेष स्वास्थ्य दल दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचकर श्रमिक भाई-बहनों को उनके कार्य एवं आवास स्थल पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। वैन में एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की जाँचें पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

साथ ही इस वैन में टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी तथा जाँच के बाद तीन महीने तक उनके स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

इसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल और चम्पावत जनपद से हो रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ''श्रमेव जयते'' का मंत्र दिया था। इसी क्रम में राज्य सरकार भी ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को केवल श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की विकासशक्ति मानती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों को उनके कार्य के लिए आवश्यक औजार, साइकिल और सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास भी कर रही है।

इसके अलावा, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने या घर खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, वृद्ध निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

इससे पूर्व बोर्ड के सचिव श्री पीसी दुम्का ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

इस मौके पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, श्री दुर्गेश्वर लाल, राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष श्री कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष श्रीमती गीता रावत, उपाध्यक्ष श्रीमती मोहनी पोखरिया, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द सिंह और सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्यांकी उपस्थित हुए।

सीएम ने वितरित की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किट

देहरादून. उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री पोषाहार योजना, शिक्षण सामग्री एवं योग आरोग्य/वेलनेस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र तथा लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किट भी वितरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारी सरकार श्रमिकों के समग्र कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।आज प्रारंभ की गई ये योजनाएं पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनेंगी। इनके माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग, पोषाहार एवं आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही योग एवं वेलनेस के माध्यम से उन्हें स्वस्थ, संतुलित और सशक्त जीवन की दिशा भी मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, दायित्वधारी कैलाश पंत भी उपस्थित रहे।

पृष्ठ 1 का शेष.....

सोनम वांगचुक का टूटा.....

उनके आंदोलन के 20 दिन सरकार ने उन्हें धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती किया था। अब उनके अनशन टूटने के बाद आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि पेपर लीक आंदोलन में विपक्ष के चक्रव्यूह में सेंध लगाने की रणनीति गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में तैयार हुई है जिसमें उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे।

अनशन तोड़ने से पहले केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो से सम्पर्क साधा था। सरकार ने उन्हें अपने स्तर पर भरोसा दिलाया और उनके माध्यम से सोनम को मनाने का प्रयास किया जो कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि सरकार वांगचुक की अधिकांश मांगों पर सहमत है और परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव होंगे। इससे वांगचुक अनशन तोड़ने पर राजी हो गए। हालांकि सोनम और आंदोलनकारियों की पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।

सोनम वांगुचक ने अनशन तोड़ने के बाद अपना वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि केंद्रिय मंत्री यहां आये थे, उनसे पहले एपेक्स बॉडी के लोग और लगभग 65 सांसदों ने हस्ताक्षर देकर अनशन तोड़ने के लिए कहा था और अब सरकार ने लिखकर आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि आंदोलन में भाग ले रहे बच्चों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। दूसरा पेपर लीक हादसे में मृत बच्चों को उचित मुआवजा दिया जायेगा। तीसरा परीक्षाओं में जवाबदेही लाने के मामले में संसद में बहस होगी और सख्त कानून लाये जायेंगे।

धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार उन्हें कोई आश्वसन नहीं दे पा रही थी पर मेरे सामने दो रास्ते थे कि मैं आगे अनशन करता और यूं ही खत्म हो जाता या फिर आपके मुताबिक ही जैसा कि कहा जाता है कि आपकी जान कीमती है। सोनम ने कहा कि यदि धमेंद्र इस्तीफा नहीं देते है तो इससे हानि बच्चों को ना होकर खुद सरकार होगी। धर्मेंद्र यदि इस्तीफा दे देते तो सरकार का नुकसान बच जाता।

पृष्ठ 1 का शेष.....

आंदोलन में राहुल के कूदने से बदल.....

सरकार विपक्ष को ये मौका नहीं देना चाहती है कि छात्रों पर राजनीति की जाये। भाजपा ने अमित शाह की अगुवाई में मैराथन बैठक करते हुए दो बिंदुओं पर कार्य किया। एक ओर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ा गया दूसरा पीएम नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्थक संदेश देना का प्रयास किया गया। नरेंद्र मोदी सेल्फी कैमरे से सोशल मीडिया पर सामने आये और अपना संबोधन को बदलते हुए नौजवान पीढ़ी से संबोधित हुए। इस पीढ़ी को यदि नरेंद्र मोदी मनाने में कामयाब हो गये तो अभी तक हुए डेमेज को संभाला जा सकता है। हालांकि सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के मूड में नहीं दिखायी दे रही है।

सम्पादकीय

नीट पेपर लीक आंदोलन और सरकार का रुख

संसद में सार्थक बहस, मीडिया में निष्पक्ष विमर्श और सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध ये तीनों लोकतंत्र के खूबसूरत स्तम्भ हैं। ये स्तम्भ ही सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। ये तीनों स्तम्भ जितने पारदर्शी उतनी ही सरकार जींवत होगी। आखिर जनता का सरोकार ही सबका लक्ष्य होता है यदि यहीं कमियां आने लगे तो किसकी आवाज उठायी जाये और किसकी आवाज सुनी जाये। पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। जिस हवा ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया वो हवा फिलहाल सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रही है।

नीट पेपर लीक से शुरू हुआ ये विवाद आज बीजेपी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। सीजेपी ने इस आंदोलन को जोड़ा और सोनम वांगचुक के आमरण अनशन से इस आंदोलन को जीवित किया और अब विपक्ष के शामिल होने से ये आंदोलन एक अलग रूप में खड़ा हो गया है। शुरूआत में सरकार को इसकी गंभीरता का अहसास हो या ना हो लेकिन अब एक स्पष्ट संदेश देना और उस संदेश पर नौजवान पीढ़ी को मनाना ये दोनों सरकार की साख का सवाल बन गये हैं। सोनम वांगचुक को तो सरकार ने किसी तरह मना लिया है। हो सकता है कि सीजेपी के अभिजीत दिपके को भी मना लिया जाये लेकिन क्या विपक्ष को मना पायेंगे क्यों कि सबकी पहली मांग की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है।

यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो एनडीए सरकार का आगे का रास्ता कठिन हो जायेगा। भाजपा सरकार को अपने इतिहास में इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने का अनुभव और आदत नहीं है। भाजपा अपने अंदाज पर राजनीति करती है। वो खुद चाहे तो कई बड़े चेहरों को घर बैठा सकती है लेकिन कोई फोर्स करके राजनीति कराना चाहे तो भाजपा ऐसी परम्पराओं की आदी नहीं है। भाजपा खुद भी जानती है कि ये दबाव धर्मेंद्र प्रधान से यदि शुरू होगा तो कहां जायेगा। ऐसे में भाजपा की कोई ऐसी इच्छा नजर नहीं आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जायेगा।

अब दूसरा पहलू ये है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए किसी तरह से भाजपा इस आंदोलन को रोकने में सफल हो गयी तो सरकार की नैतिक जीत मानी जायेगी। इस विश्वास को लौटाने के लिए और युवाओं के दिल में भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी का विश्वास बनाये रखने के लिए एक बार फिर मोर्चा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संभाला हैं। एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा की फास्ट टैक कोर्ट का गठन किया जायेगा फिर उन्होंने अगले दिन सोशल मीडिया पर सेल्फी कैमरे से वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में उनका अंदाज नया था जो पूरी तरह युवाओं पर केंद्रित था। इन्हें ही तो मनाना है।

दूसरी ओर राहुल गांधी के पीछे पूरा विपक्ष लामबद्ध हो रहा है। अचानक पीएम आवास का घेराव, पुलिस का जबरदस्ती डिटेन करना, नाक पर खून का निशान। ये सब आंदोलन को अलग रूख दे रहा थे। दूसरे दिन बस में सवार होकर गांधी स्मृति जाना ये सब आंदोलन को मजबूत करने जैसा था। अब लोगों को सरकार की पशोपेश खत्म होने का इंतेजार है। हो सकता है नकल कानून या पेपर लीक कानून को ओर कड़ा कर दिया जाये लेकिन युवाओं का विश्वास जीतना और और उसे बनाये रखना बड़ी बात होगी।

गौरवपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्यों का साझा करने का अवसर

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पर अमृत महोत्सव का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया में हमारे देष की लोकतंत्र की जड़े सबसे गहरी होने के साथ ही आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से भारत दुनिया के देषों के सामने एक मिसाल है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल से जिस तरह से 15 जुलाई, 2026 को आयोजित अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में विधानसभा के नए पुराने सदस्यों को

एक साझा मंच उपलब्ध कराने और एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराया है वहीं उच्च सदन के सभापति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र और समापन सत्र में सहभागी बनाकर कार्यक्रम को और अधिक गरिमामय बनाया है। अमृत महोत्सव में राजस्थान विधानसभा के 410 नए पुराने सदस्यों ने हिस्सा लिया वहीं 6 बार या इससे अधिक समय तक सदस्य रहे सम्माननीयों का सम्मान कर लोकतांत्रिक मूल्यों का ही स्वागत सम्मान किया गया है।आज जिस तरह से विधायिका की कम बैठकों, सत्रों के दौरान हंगामें के हालात और मतभेद और मनभेद के हालातों में राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव केवल एक आयोजन ना होकर नए विधायकों के लिए प्रेरणास्पद भी हो गया है। अमृत महोत्सव के दौरान राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनकारी 24 कानूनों पर चर्चा भी की गई तो नए पुराने सदस्यों के अनुभवों को साझा करने का भी बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सका है। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिमार्केवल प्रतिक्रिया दी कि चुनाव भले ही वोट के आधार पर जीते जाते हैं पर जनता का दिल तो लोकहितकारी कार्य करके ही जीता जा सकता है। संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति गरिमा बनाये रखने में हैं वहीं बहस की गुणवत्ता, गंभीरता और सदन में आचरण की मर्यादा से ही संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं और उनका मानना रहा कि विधानसभा उनके लिए संस्कारों की पाठशाला रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि दुश्मनी जमकर करों पर खिड़की भी खुली रखों। इंसानियत राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने स्व. भैरोसिंह शेखावत और स्व. मोहन लाल सुखाड़िया व स्व. भैरोसिंह शेखावत व स्व. हरिदेव जोशी के बीच सदन और सदन के बाहर के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि संबंधों की लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघा जाना चाहिए। मतभेद भले ही हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर आयोजित अमृत महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सहित पक्ष विपक्ष के नेताओं ने खुलकर विचार रखते हुए विधायिका की कम बैठकों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्यत: इस तरह के कार्यक्रम मात्र औपचारिकता बन कर रह जाते हैं पर जिस तरह से अमृत महोत्सव को लोकतंत्र के लिए उपादेय, लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, सत्र के दौरान बहस के स्तर की गंभीरता, दलगत राजनीति से उठकर साझा मंच पर खुली चर्चा और अनुभवों का साझा करने से यह आयोजन विशिष्ठ आयोजन हो जाता है। जिस तरह से सत्रों के दौरान हंगामें के हालात बनते हैं और आपसी मतभेद और मनभेद की स्थितियां होने लगी है इस पर चिंता व्यक्त करने के साथ ही विधानसभा के पहले के सत्रों में गंभीरता, तथ्यात्मकता, गहन अध्ययन और स्तरीय बहसों के उदाहरण उद्दृत करते हुए गंभीर और स्तरीय बहस पर जोर दिया गया। यहां तक कहा गया कि हंगामें से नहीं तथ्य और तर्क व संवाद से बड़े नेता बनते हैं। लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा से इंसानियत की भावना पर जोर दिया गया। प्रचारअभियान और चुनावअमृत महोत्सव के बहाने जिस तरह से सदनों में बहस के दौरान पक्ष-विपक्ष के सदस्यों द्वारा गरिमापूर्ण, गंभीरता परक, गहन अध्ययन, आलोचना के लिए आलोचना ना होने, तथ्यपरक पक्ष रखने और गंभीर बहस से सदन की गरिमा ही बढ़ेगी और इसका लाभ लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करने में मिल सकेगा। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का यह कहना कि अनुभव और युवा उर्जा का समागम ही लोकतंत्र की असली पूंजी है। देखा जाए तो राजस्थान विधानसभा के अमृत उत्सव का यह आयोजन जहां लोकतंत्र की मजबूती, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही लोकतंत्र में अटूट आस्था, गौरवशाली लोकतांत्रिक आस्था का माध्यम बन गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह निकश की यह आयोजन अतीत का उत्सव ही नहीं अपितु भविष्य का पथ-प्रदर्शक भी है। राजस्थान विधानसभा के इस अमृत महोत्सव पर जिस तरह से सत्रों के दौरान बहस को स्तरीय बनाने, हंगामें की भेंट नहीं चढ़ाने, गहन अध्ययन और तर्क आधारित बहस और पूरी तैयारी के साथ सदन में हिस्सा लेने पर जिस तरह का एक स्वर में संदेश दिया गया है और जिस तरह से विचारधारा और प्रतिवद्धता भिन्न होने के बावजूद मानवीय संबंधों को बनाये रखने यानी की मतभेद के बावजूद मनभेद नहीं रखने का गंभीर व संदेश दिया गया है।

अमृत महोत्सव में अभी चार कार्यक्रम और होने है और कार्यक्रमों पर आमजन की निगाहें इस मायने में हैं कि सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही आमनागरिकों केन्द्र में होना चाहिए। आयोजन के लिए साधुवाद इस अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि नए सदस्यों को गरिमापूर्ण इतिहास से रुबरु होने के साथ ही वरिष्ठों के अनुभवों को भी साझा और आत्मसात करने का अवसर मिल रहा है। सही मायने में विधायी परंपरा को समझने, संसदीय मर्यादाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर अनुभवों को साझा करने का अवसर मिला है।

सड़कों पर पड़ा कंस्ट्रक्शन मटीरियल हटाए जाने के निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम की संचालन समिति की सातवीं बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने प्रदेश के तीन शहरों देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी ली और सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि तीनों शहरों में वायु गुणवत्ता की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। मुख्य सचिव ने पीएम 10 और पीएम 2.5 को कम किए जाने के लिए सभी उपायों पर कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम 10 को कम करने के लिए शहरों की सड़कों की स्थिति को सुधारे जाने के साथ ही, धूल कणों को कम किए जाने वाले उपायों को शामिल किया जाए।

उन्होंने सभी सड़कों का पक्कीकरण, फुटपाथों के निर्माण कार्य आदि पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि डेमोलिशन वेस्ट के लिए प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने सभी स्थानीय निकायों को डेमोलिशन वेस्ट के लिए उचित निस्तारण स्थल चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इसका उचित प्रचार प्रसार भी किया जाए ताकि भवनों को ध्वस्त किए जाने के बाद अपशिष्ट को कहां डिस्पोज किया जाना है, आमजन को पता होना चाहिए।

मुख्य सचिव ने सड़कों पर पड़ा कंस्ट्रक्शन मटीरियल हटाए जाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पीएम 2.5 को कम करने के लिए वाहनों एवं फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने वाले उपाय अपनाने की बात कही। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इसके लिए पीसीबी को मैनपावर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जाममुक्त सड़कों के लिए चौक सुधारीकरण कार्य किए जाएं। उन्होंने पिछले वर्षों की तुलना में काशीपुर पीएम 2.5 में सुधार आने के कारणों का विश्लेषण कर अन्य शहरों में उसे लागू किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन शहरों के सुधार कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाए। मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छे प्रस्ताव तैयार किए जाए। उनकी प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सभी प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किए जाने पर मुख्य सचिव ने जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों में डिस्प्ले बोर्ड में प्रदर्शन किया जाए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी डिस्प्ले बोर्ड्स को एक्टिव किया जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सदस्य सचिव यूकेपीसीबी डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं अपर सचिव डॉ. आनन्द श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एसपी चमोली की अध्यक्षता में आयोजित की गयी अपराध गोष्ठी

चमोली। आज पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, स्थानीय अभिसूचना इकाई, फायर सर्विस, दूरसंचार एवं अन्य शाखा प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित कर मासिक अपराधों की समीक्षा एवं कर्मचारियों के साथ सम्मेलन किया गया। गोष्ठी में जनपद में घटित मासिक अपराधों, कानून-व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं, यात्रा तथा विभिन्न अभियानों की विस्तार से समीक्षा की गई। एसपी चमोली ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण एवं प्रभावी पुलिसिंग के लिए सतर्क, सक्रिय एवं जवाबदेह रहने के निर्देश दिए। इस दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए- गोष्ठी के दौरान सर्वप्रथम एसपी चमोली ने जनपद के विभिन्न थानों/शाखाओं से आए पुलिस कर्मियों का सम्मेलन आयोजित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना। कर्मचारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के त्वरित एवं यथासंभव मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस कर्मी की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा उनके निराकरण हेतु हर स्तर पर हरसंभव प्रयास किए जाएंगे, जिससे पुलिस बल का मनोबल एवं कार्यक्षमता निरंतर बनी रहे। तत्पश्चात माह जून की मासिक अपराध गोष्ठी में दिए गए एजेंडा बिंदुओं के अनुपालन की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि डल्ड, ळल्ड, समन्वय पोर्टल एवं सहयोग पोर्टल का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इन पोर्टलों पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना, शिकायत एवं संदर्भ का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं विधिसम्मत निस्तारण किया जाए। किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक प्रकरण का नियमित फॉलोअप कर पोर्टलों पर अद्यतन प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से की जाएं। जनपद में लगातार हो रही भारी वर्षा एवं संभावित प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत समस्त थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आपदा राहत उपकरणों को 24ञ7 क्रियाशील रखा जाए तथा एसडीआरएफ, फायर सर्विस एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाएं। सभी थाना क्षेत्रों के संवेदनशील एवं भूस्खलन संभावित स्थानों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार निगरानी रखने, मार्ग अवरुद्ध होने पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खुलवाने और सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए गए। मासिक अपराधों की समीक्षा करते हुये लम्बित विवेचनाओं, शिकायती प्रार्थना पत्रों, समन, वारण्ट आदि के समय से निस्तारण करने एवं वांछित अभियुक्तों की धर-पकड़ अभियान में और अधिक तेजी लाने तथा अवैध नशा कारोबारियों के विरूद्ध सक्रिय रहकर कठोर कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये साथ ही वित्तीय/साईबर धोखाधडी एवं महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुये विवेचना में गुणवत्ता एवं सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिलाओं से संबंधित प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता, गंभीरता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पीड़ित महिला को तत्काल आवश्यक कानूनी, सुरक्षा एवं अन्य हरसंभव सहायता उपलब्ध किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। ष्ऑपरेशन प्रहारष के अंतर्गत फरार, वांछित, इनामी एवं पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी, सत्यापन अभियान एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सघन चालानी अभियान चलाकर अधिक से अधिक चालान एवं आवश्यकतानुसार वाहन सीज की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

'रन फॉर कारगिल हीरोज', शौर्य दिवस के अवसर पर कारगिल वीरों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल दिवस को इस वर्ष भी 'शौर्य दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। शौर्य दिवस के एक दिन पूर्व, 25 जुलाई 2026 (शनिवार) को देहरादून में 'रन फॉर कारगिल हीरोज' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसामान्य, विशेषकर युवाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है।

कारगिल के अमर शहीदों के सम्मान में आयोजित स्मृति एवं श्रद्धांजलि रन होगा, जिसमें सभी प्रतिभागी निर्धारित मार्ग पर सामूहिक रूप से सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में श्रेणियों के प्रतिभागियों में ओपन पुरुष एवं महिला वर्ग (18 वर्ष एवं अधिक), विद्यालय वर्ग (बालक/बालिका) कक्षा 9 से 12, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पुरूष एवं महिला वर्ग, पूर्व सैनिक, वीर नारियों एवं शहीद आश्रित (सांकेतिक रन /वॉक, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, इच्छुक दिव्यांगजन (समावेशी रन/वॉक, वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष एवं अधिक) (रन वॉक)।

25 जुलाई को प्रात: 07 बजे प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं एकत्रीकरण टी-शर्ट कैप वितरण, शौर्य स्थल, चीड़बाग, प्रात: 07:45 बजे कारगिल शहीदों को पुष्पांजलि, प्रात: 08 बजे माननीय मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रन का शुभारंभ प्रात: 09:30 बजे गांधी पार्क, देहरादून में रन का समापन। रन फॉर कारगिल हीरोज से शौर्य स्थल, चीड़बाग- राजपुर रोड - गांधी पार्क, देहरादून पर समापन किया जाएगा।दौड़ की विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दिनांक 26 जुलाई 2026 को आयोजित शौर्य दिवस के मुख्य समारोह में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने पुलिस एवं यातायात विभाग मार्ग पर सुरक्षा, पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के निर्देश दिए। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, देहरादून को नोडल अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को प्रभारी अधिकारी तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून को ओवरऑल नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

जिला प्रशासन ने पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स, विद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, पुलिस एवं सुरक्षा बलों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, युवा संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की अपील की है, ताकि कारगिल के अमर वीरों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की भावनाओं को सामूहिक रूप से अभिव्यक्त किया जा सके।

फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध एवं कठोर दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

केंद्रीय संचार ब्यूरो का तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का समापन

संवाददाता

देहरादून। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो, देहरादून द्वारा चिल्ड्रन्स पार्क, चकराता में आयोजित 'विकसित भारत ख़ गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' विषय पर तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का गुरुवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिताओं, चित्र प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, जन-जागरूकता गतिविधियों तथा विभिन्न विभागों के सूचना स्टॉलों के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं आमजन को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया गया।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि कैंट बोर्ड, चकराता के उपाध्यक्ष श्री अनिल चांदना ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे स्वयं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और समाज के अन्य लोगों को भी इनके प्रति जागरूक कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया।

समापन समारोह में कैंट इंटर कॉलेज, चकराता के छात्र-छात्राओं ने भाषण, पेंटिंग एवं क्विज प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित 'विकसित भारतख़ गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' विषयक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सूचना स्टॉलों से सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के दूसरे दिन जौनसार पब्लिक स्कूल, चकराता के विद्यार्थियों ने चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत योग एवं नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहीं। तीसरे दिन कैंट इण्टर कॉलेज के छात्रों ने जौनसारी लोक नृत्य पेश कर समां बंधा।

दूसरे दिन की मुख्य अतिथि एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मृदुला थापा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं।

कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विभागों की प्रमुख योजनाओं, सेवाओं एवं लाभार्थी कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं, बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए सूचना स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाया।

चकराता में आयोजित तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत "नशा मुक्त भारत अभियान" विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में जौनसार पब्लिक स्कूल के जूनियर एवं सीनियर वर्ग और कैंट इण्टर कॉलेज के विजेताओं को मुख्य अतिथि अनिल चांदना ने पुरस्कार दे कर सम्मानित किया।

सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (यूटीयू) की सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त द्वारा परीक्षा से पूर्व ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परीक्षा से जुडे प्रश्नपत्रों को लीक किया गया था। आज वादी डॉ विनय कुमार पटेल परीक्षा नियंत्रक वीर माधव सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा कोतवाली प्रेमनगर में लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में बताया गया कि उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सम-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान दिनांक 08-07-26 को आयोजित परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को एक ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक 03-07-26 को शिवालिक कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग देहरादून में नियुक्त सहायक प्रोफेसर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर किए जाने की जानकारी दी गई, जिसका परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो उक्त प्रश्नों में काफी समानता पाई गई। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित की गई आन्तरिक जांच समिति की जांच के दौरान भी उक्त सहायक प्रोफेसर द्वारा परीक्षा से पूर्व छात्रों के आन्तरिक पोर्टल/व्हाट्सएप पर परीक्षा से सम्बन्धित समान प्रश्नों को साझा किया जाना प्रकाश में आया। शिवालिक कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग में नियुक्त सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता द्वारा छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता को भंग किया गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर पर मु0अ0सं0 / 144/26 धारा/ 316, 318 (4), 61 (2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा अभियोग में त्वरित साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियोग में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिस पर विवेचक द्वारा अभियोग में गवाहों के बयान, प्राप्त दस्तावेजी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में नामजद अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर शिवालिक कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग झाझरा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से प्राप्त उपकरणों के संबंध में जांच की जा रही है तथा उक्त प्रकरण में सलिप्त अन्य अभियुक्त गणों के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आशीष कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर शिवालिक कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग शाकुम्भरी विहार सहारनपुर का मूल निवासी है।

गढ़वाल मंडलायुक्त ने की गति की समीक्षा

पौड़ी। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने मंडलीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंशन योजनाओं में डुप्लीकेसी समाप्त करने, आधार सीडिंग में तेजी लाने, टीबी प्रभावित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत एक्स-रे, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, निर्माणाधीन राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा पैक्स को जन सुविधा केंद्र संचालन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए जनपदवार रोस्टर तैयार करने को कहा।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने किसान पेंशन लाभार्थियों का अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से मिलान कर डुप्लीकेसी समाप्त करने के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाने तथा पात्र लाभार्थियों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाभार्थियों की पहचान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लेने को भी कहा।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप मासिक लक्ष्य निर्धारित कर नियमित निगरानी एवं समयबद्ध उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा टीबी के चिन्हित हाई-रिस्क गांवों में शत-प्रतिशत एक्स-रे कराने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी विद्यालय भवनों एवं शौचालयों को स्वच्छ, सुरक्षित और उपयोग योग्य बनाए रखने तथा आवश्यकता होने पर तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।

चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में निर्माणाधीन राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। साथ ही रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी-भरदार स्थित निर्माणाधीन विद्यालय का तृतीय पक्ष निरीक्षण कर गुणवत्ता एवं प्रगति का स्वतंत्र आकलन कराने को कहा।

सहकारिता विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने पैक्स को जन सुविधा केंद्रों के संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जनपदवार प्रशिक्षण रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायत राज, ग्रामीण विकास, आयुष, युवा कल्याण एवं प्राविधिक शिक्षा विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. आर. सी. पंत, अपर निदेशक अर्थ एवं संख्या गीतांजलि शर्मा, अपर निदेशक शिक्षा पी. के. बिष्ट, अपर निदेशक तकनीकी शिक्षा देवेंद्र गिरी, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास की कीमत पर प्राकृतिक विरासत का विनाश मंजूर नहीं

देहरादून। राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा संघ, उत्तराखंड ने भानियावाला- ऋषिकेश रोड क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरोध में चल रहे शांतिपूर्ण अनशन और धरना-प्रदर्शन को अपना पूर्ण समर्थन घोषित किया है। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मलिक ने कहा कि विकास की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विकास की कीमत हमारी प्राकृतिक विरासत और पर्यावरण को नष्ट करके नहीं चुकाई जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष रेशू कुमार चौधरी ने पर्यावरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पेड़ केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं। यह हमारे जीवन, जल, वायु और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार हैं। उन्होंने मांग की कि सड़क विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा संघ ने सरकार और संबंधित अधि कारियों से अपील की है कि ऋषिकेश रोड परियोजना में पर्यावरणीय प्रभाव का गंभीरता से आकलन किया जाए। पेड़ों की कटाई को कम से कम (न्यूनतम) किया जाए। सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित कर एक बीच का रास्ता निकाला जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नहीं है। यह प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रयास है।

फिल्म क्रांतिवीर के पूरे हो गए 32 साल

नई दिल्ली। क्रान्तिवीर 1994 में बनी हिन्दी भाषा की अपराधिक पृष्ठभूमि की एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन मेहुल कुमार ने किया और फिल्म में नाना पाटेकर, डिंपल कपाड़िया, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी, डैनी डेन्जोंगपा और परेश रावल प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह वर्ष की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, इसके अलावा इसने तीन स्टार स्क्रीन पुरस्कार, चार फिल्मफेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म सुपरहिट रही थी। प्रताप तिलक (नाना पाटेकर), स्वतंत्रता सेनानी भीष्मनारायण तिलक का पोता है। प्रताप जुआ खेलना शुरू कर देता है। प्रताप की मां दुर्गादेवी (फरीदा जलाल) इन सब से गुस्सा रहती है और उसे गांव छोड़ने के लिए कहती है। प्रताप मुंबई आता है जहां वह चॉल मालिक, लक्ष्मीदास (परेश रावल) के बेटे अतुल (अतुल अग्निहोत्री) का जीवन बचाता है। लक्ष्मीदास प्रताप को अपने साथ रखने का फैसला करता है। बड़े होने पे अतुल, ममता (ममता कुलकर्णी) से प्यार करता है जो योगराज (टीनू आनंद) नामक एक बिल्डर की बेटी है। इस बीच प्रताप, प्रेस रिपोर्टर मेघा दीक्षित (डिंपल कपाड़िया) पर हँसता रहता है जो चॉल में रहती है और समाचार पत्रों में लिखकर अन्याय से लड़ना चाहती है। प्रताप लोगों को मजबूत बनना और दूसरे लोगों से मदद की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद के लिए लड़ना सिखाता है। जबकि चतुरसिंह (डैनी डेन्जोंगपा) और योगराज चॉल पर एक रिसॉर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं। वे सांप्रदायिक दंगे, सामूहिक हत्याएँ और लोगों के घरों को जलाते हैं। चतुरसिंह द्वारा लक्ष्मीदास की हत्या कर दी जाती है। प्रताप को ये भी पता चलता है कि चतुरसिंह ने मेघा के माता-पिता की हत्या कर दी थी और उसके साथ बलात्कार किया था। वह मेघा से शादी का प्रस्ताव रखता है। ममता अपने पिता का घर छोड़ती है और अतुल के घर आ जाती है। प्रताप भ्रष्ट मंत्रियों, न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी को मारता है। वह पकड़ा जाता है। चतुरसिंह प्रताप को मारने की योजना बनाता है, लेकिन प्रताप के हाथों मारा जाता है। प्रताप के खिलाफ मुकदमा चलता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। आखिरी पल में, उसे फांसी देने से पहले एक वकील आता है, यह बताते हुए कि प्रताप का मृत्युदंड सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। फिल्म के साउंडट्रैक में 6 गाने हैं। समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ संगीत आनंद-मिलिंद द्वारा दिया गया है।

ष्नाना से कहा गया कि तुम्हारा एक भी नया कपड़ा नहीं बनाया जाएगा। तुम अपने पुराने कपड़े हमें लाकर दो। उन्हीं को हम रेडी करेंगे। और चूंकि तुम्हारा किरदार खटिया पर सोता है तो कपड़ों पर प्रैस भी नहीं होगी।ष ये बात मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर से उस समय कही थी जब वो नाना को क्रांतिवीर की कहानी सुनाने जा रहे थे। हालांकि मेहुल कुमार को डर था कि कहीं नाना इन्कार ना कर दें। लेकिन नाना ने इन्कार नहीं किया। बल्कि पूरी दिलचस्पी वो उस किरदार में ले रहे थे। कपड़े तो छोड़िए, फिल्म में क्रांतिवीर में आपने नाना को जिन चप्पलों में देखा था वो भी उनके खुद के थे। फिल्म जब रिलीज होकर सफल हो गई तो डायरेक्टर मेहुल कुमार ने नाना को कई जोड़े नए कपड़े बनाकर दिए। मेहुल कुमार ने स्वंय ये बात एक इंटरव्यू में बताई। क्रांतिवीर के 32 साल पूरे हो गए हैं आज। 22 जुलाई 1994 को क्रांतिवीर रिलीज हुई थी। बड़ी शानदार फिल्म है। आज भी कोई क्लिप इंटरनेट पर देखने को मिल जाती है तो लोग वो पूरी क्लिप देखना पसंद करते हैं। चलिए साथियों, इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां जानते हैं। क्रांतिवीर उस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्म थी। तीन करोड़ रुपए के बजट में बनी क्रांतिवीर ने 20 करोड़ 67 लाख रुपए की बंपर कमाई की थी। उस साल पहले नंबर पर सलमान खान की हम आपके हैं कौन रही थी। दूसरे नंबर पर थी अक्षय और सुनील शेट्टी की मोहरा। कहीं-कहीं क्रांतिवीर को 1994 की दूसरी सबसे सफल फिल्म बताया जाता। है। लेकिन वो गलत है। क्रांतिवीर तीसरे नंबर पर रही थी। चौथे नंबर गोविंदा की राजा बाबू थी। मेहुल कुमार का उन दिनों कुछ ऐसा जलवा था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जैसे ही पता चलता था कि मेहुल कुमार कोई फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, वो पैसा लेकर उनके पास पहुंच जाते थे। जिस दिन क्रांतिवीर का मुहुर्त था उस दिन भी मेहुल कुमार के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स आए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म में नाना पाटेकर के हीरो होने पर आपत्ति थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स मेहुल कुमार से कहा कि आपने तिरंगा में नाना को लिया था और वो फिल्म चल भी गई थी। क्योंकि उसमें राज कुमार थे। लेकिन इस फिल्म में कोई सिर्फ नाना को क्यों देखने आएगा? आपने तो कोई बड़ा स्टार भी नहीं लिया है फिल्म में। मेहुल कुमार ने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहा कि नाना पाटेकर ही उस कैरेक्टर में फिट बैठते हैं। कोई और नहीं। मेहुल कुमार ने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से ये भी कहा कि आप पैसा मत दीजिए। जिस दिन फिल्म कंप्लीट हो जाएगी उस दिन फिल्म देखकर पैसा दीजिएगा। ये था नाना पाटेकर के टैलेंट पर मेहुल कुमार का भरोसा। मेहुल कुमार ने जब डिंपल कपाडिया को उनका कैरेक्टर नैरेट किया था तब डिंपल जी काफी कन्फ्यूज हो गई थी। क्योंकि वो एकदम नॉन ग्लैमरस कैरेक्टर था। जबकी डिंपल जी को लगा था कि उन्हें कोई ऐसा कैरेक्टर ऑफर होगा जो फुल ऑफ ग्लैमर हो। उन्होंने अपने संकोच का जिक्र जब मेहुल कुमार से किया तो मेहुल जी ने उन्हें समझाया कि आप एक पोटेंशियल एक्ट्रेस हो। इसलिए इस तरह के किरदार भी आप निभा सकती हो। और लोग आपको ऐसे किरदारों में भी पसंद करेंगे। डिंपल को मेहुल भाई की बात समझ में आई और उन्होंने क्रांतिवीर साइन कर ली। और कमाल देखिए, आज भी कई लोग डिंपल जी को क्रांतिवीर की कलम वाली बाई कहते हैं। क्रांतिवीर के कई आइकॉनिक सीन्स में से एक था वो वाला सीन जिसमें नाना पाटेकर अपनी और उल्लास की उंगली पत्थर से फोड़कर, और फिर दोनों का खून मिलाकर उससे पूछते हैं कि बता इसमें कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का है। ये सीन जब चांदीवली स्टूडियो में पिक्चराइज किया जा रहा था उस वक्त लगभग 500 जूनियर आर्टिस्ट बुलाए गए थे। एक इंटरव्यू में मेहुल कुमार जी ने उस सीन को याद करते हुए बताया था कि जब नाना पाटेकर को ये सीन सुनाया गया था तो वो बहुत खुश हुए थे। उन्हें वो सीन काफी पसंद आया था। जिस दिन चांदिवली स्टूडियो में सीन फिल्माया जा रहा था उस दिन अच्छी-खासी भीड़ वहां थी। लेकिन ये सीन शूट करते वक्त हर कोई शांत था। सब चुपचाप इस सीन को शूट करते नाना पाटेकर को देख रहे थे।

पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ दिया... जंतर-मंतर पर डटे छात्रों के समर्थन में आई Alia Bhatt, लिखा भावुक नोट!

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक के विरोध में चल रहा छात्रों का प्रदर्शन अब व्यापक रूप लेता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नीट (NEET-UG) पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में अब बॉलीवुड हस्तियां भी खुलकर सामने आने लगी हैं। अभिनेता सलमान खान के बाद अब प्रसिद्ध अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी छात्रों के समर्थन में एक बेहद भावुक और विचारणीय संदेश साझा किया है।

दिल्ली में छात्र विरोध प्रदर्शन का आलिया भट्ट ने किया समर्थन

सलमान खान के बाद, आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन के बीच एक नोट लिखा। उन्होंने लिखा, ष्पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ा है और फिर उम्मीद के साथ उसे बार-बार जोड़ा भी है। अपनी बात पर अड़े हर छात्र के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत बलिदानों का सफर है। वे न केवल खुद का, बल्कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है, साथ ही वे उन लोगों के लिए एक बेहतर रास्ता बना रहे हैं जो उनके बाद आएंगे।ष

एक्ट्रेस ने आगे कहा, उनकी हिम्मत मुझे विनम्र बनाती है। उनका संकल्प हम सभी के लिए एक आईने की तरह है, जो हमसे पूछता है कि क्या हम सच में उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो इस देश के कल को आकार देंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। छात्रों के लिए। छात्रों द्वारा। भविष्य उन्हीं का है। जय हिंद।

छात्र विरोध प्रदर्शन पर सलमान खान ने क्या पोस्ट किया?

22 जुलाई की देर रात, सलमान खान ने ग पर विरोध प्रदर्शनों के बारे में एक नोट लिखा। उनके नोट का एक अंश इस प्रकार था: ष्यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच है, इसे राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए, इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को जाना चाहिए, और मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और इसे एक मजबूत शिक्षा प्रणाली बनाएगी। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति है। सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान उन सभी पर कृपा बनाए रखे जो शिक्षित होना चाहते हैं। शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए, और इसे साल-दर-साल और अधिक ट्रेंडी और फैशनेबल बनना चाहिए, इतना कि बाहर से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक शैक्षिक केंद्र बन जाए।ष

दिल्ली में छात्र विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?

दिल्ली में छात्र NEET UG सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले दस सालों में देश भर में 152 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बार-बार हो रही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदारी तय करने के मकसद से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि पेपर लीक के कथित मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि NEET UG पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी।

उपराष्ट्रपति ने कोयंबटूर में जीकेएनएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज कुशल, संवेदनशील और सेवा-भाव वाले वर्कफोर्स के जरिए भारत के हेल्थकेयर इकोसिस्टम को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली हेल्थकेयर और शिक्षा एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र के दो मुख्य आधार हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक श्विकसित भारतश की ओर देश की यात्रा के लिए हेल्थकेयर डिलीवरी को बेहतर बनाने, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारी से बचाव वाली स्वास्थ्य सेवा) को बढ़ावा देने और समर्पित हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत होगी। कोयंबटूर में जीकेएनएम ग्रुप कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस संस्थान को जीकेएनएम ग्रुप की जन-सेवा की लंबी परंपरा में एक और मील का पत्थर बताया। उन्होंने पिछले कई दशकों से हेल्थकेयर और शिक्षा के क्षेत्र में जी . कुप्पुस्वामी नायडू चौरिटेबल ट्रस्ट के शानदार योगदान की सराहना की।

उन्होंने बताया कि 1952 में शुरू हुआ उनका 50 बिस्तरों वाला अस्पताल आज 750 बिस्तरों वाले मल्टी-स्पेशलिटी संस्थान के रूप में विकसित हो गया है और साथ ही उनके शैक्षिक प्रयास स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक फैल गए हैं। नर्सिंग पेशे के महत्व पर जोर देते हुए, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि नर्सें सिर्फ देखभाल करने वालों से कहीं बढ़कर होती हैं। उन्होंने कहा, ष्वे मरीजों को सुरक्षित और अच्छी देखभाल का एहसास कराती हैं। दवाओं के साथ-साथ, उनकी करुणा और चिंता भी ठीक होने में अहम भूमिका निभाती है।'' उन्होंने इस पेशे में आने वाले छात्रों से अपनी जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास, संवेदना, समर्पण और साहस के साथ निभाने और हमेशा अपने पेशे की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। भारत के हेल्थकेयर सेक्टर में हो रहे बदलावों पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम ने अच्छी गुणवत्ता वाली हेल्थकेयर तक पहुँच बढ़ाने के लिए वैश्विक पहचान हासिल की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 44 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिला है। बुजुर्गों के लिए हेल्थकेयर पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ''प्रधानमंत्री वय वंदना योजनाश के तहत मुफ्त हेल्थकेयर और हेल्थ सर्विस के डिजिटाइजेशन से देश भर में अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर ज्यादा लोगों तक पहुँच रही है।

उपराष्ट्रपति ने प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारी से बचाव वाली स्वास्थ्य सेवा) के महत्व पर जोर दिया और महिलाओं व बच्चों में एनीमिया को खत्म करने, सुरक्षित गर्भावस्था सुनिश्चित करने और बचपन से किशोरावस्था तक बेहतर न्यूट्रिशन के लिए मिलकर कोशिशें करने का आह्वान किया।

उन्होंने अंग और नेत्र दान के बारे में लोगों में ज्यादा जागरूकता लाने की भी अपील की और इसे नेक काम बताया, जिससे जानें बचती हैं और उम्मीदें फिर से जागती हैं। श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि जीकेएनएम ग्रुप हेल्थकेयर और शिक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के जरिए इन आदर्शों को अपनाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि हाल ही में शुरू हुआ नर्सिंग कॉलेज ऐसे काबिल और संवेदनशील हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार करेगा जो देश के निर्माण में अहम योगदान देंगे।

उपराष्ट्रपति ने जीकेएनएम ग्रुप के ट्रस्टियों, मैनेजमेंट, फैकल्टी, नर्सों, छात्रों और स्टाफ को बधाई दी और हेल्थकेयर व शिक्षा में बेहतरीन काम के जरिए समाज की सेवा करने के संस्थान के मिशन में लगातार सफलता की कामना की। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि जी. कुप्पुस्वामी नायडू चौरिटेबल ट्रस्ट जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज शुरू करेगा, जो सेवा की भावना रखने वाले और सबसे गरीब व निर्बल लोगों की देखभाल के लिए समर्पित कुशल मेडिकल प्रोफेशनल तैयार करेगा।

इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर; कुप्पुस्वामी नायडू चौरिटी ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ के अध्यक्ष श्री आर. गोपीनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

एपीडा ने उत्तराखंड से इराक के लिए 24 टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के पहले निर्यात को सुगम बनाया

नई दिल्ली। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से इराक को 24 टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के पहले निर्यात में सहायता प्रदान की है। वीरुन ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई यह खेप उत्तराखंड से मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निर्यातक ने विश्वास व्यक्त किया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद से बार-बार ऑर्डर मिलेंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे, जिससे कंपनी और क्षेत्र के लिए निर्यात के निरंतर अवसर पैदा होंगे। एपीडा ने निर्यातक को सियाल, गल्फूड, इंडसफूड और वर्ल्ड फूड इंडिया सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहयोग दिया है, जिससे बाजार तक व्यापक पहुंच और खरीदारों के साथ बेहतर जुड़ाव संभव हुआ है।भारत प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को लगातार सुदृढ कर रहा है। 2025-26 के दौरान, प्रसंस्कृत सब्जियों का भारत का निर्यात 932.25 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 7,26,874.70 एमटी उत्पाद शामिल थे। इसमें से, मूल्यवर्धित आलू उत्पादों का निर्यात 277,108.51 एमटी था, जिसका मूल्य 289.40 मिलियन डॉलर था। प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों ने मिलकर वर्ष के दौरान एपीडा के निधरित निर्यात में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान दिया। एपीडा अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने कहा कि उत्तराखंड जैसे भू-आबद्ध राज्यों से निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर लॉजिस्टिक्स लागत का लगातार प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एपीडा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और निर्यातकों के लिए अधिक बाजार पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से परिवहन सहायता प्रावधानों सहित राज्य कृषि निर्यात नीति के निर्माण और कार्यान्वयन पर उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उत्तराखंड में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग का विस्तार गुणवत्तापूर्ण कच्चे उत्पादों की निरंतर मांग सृजित करके, स्रोत स्तर पर मूल्यवधरन को बढ़ावा देकर और निर्यात-उन्मुख आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके कृषि मूल्य श्रृंखला में मजबूत बाजार अवसर पैदा कर रहा है। ऐसी पहलों से और बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ राज्य के प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एपीडा निर्यात अवसंरचना को सुदृढ़ करने, वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाने और भारत से मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्रसंस्करणकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर मिलकर काम कर रहा है।

आयुष उपचार सेवाओं के विस्तार के संबंध में रक्षा मंत्री को पत्र लिखा

नई दिल्ली। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सैन्य और फील्ड अस्पतालों में आयुष ओपीडी की स्थापना और आयुष आधारित उपचार सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने अपने संदेश में विभिन्न और अक्सर चुनौतीपूर्ण सैन्य परिस्थितियों में सेवारत देश के सैनिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है। श्री जाधव ने कहा कि यद्यपि सशस्त्र बलों के पास एक मजबूत आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना है, फिर भी भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को इसमें शामिल करने से रक्षा कर्मियों के लिए निवारक, संवर्धक और समग्र स्वास्थ्य सेवा को और अधिक मजबूती मिल सकती है। श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन कुछ ही संस्थानों में आयुष उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में सैन्य और क्षेत्रीय अस्पतालों में अभी तक आयुष सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का विस्तार करने से सैनिकों को साक्ष्य-आधारित पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से निवारक स्वास्थ्य देखभाल, जीवनशैली प्रबंधन, पुनर्वास और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अधिक पहुंच सुनिश्चित होगी। श्री जाधव ने इस बात पर बल दिया है कि आयुष सेवाओं को शामिल करने से मौजूदा स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूती मिलेगी और सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अधिक व्यापक और रोगी-केंद्रित देखभाल मॉडल विकसित करने में योगदान मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहल से भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा विरासत को देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से सभी सैन्य एवं फील्ड अस्पतालों में आयुष ओपीडी और उपचार सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयुष मंत्रालय इस पहल के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सभी तकनीकी सहायता, व्यावसायिक मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी शामिल है।

ओलंपियाड में भारत की युवा प्रतिभा का जलवा

नई दिल्ली। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने एक बार फिर से देश की वैज्ञानिक प्रतिभाओं के संवर्धन में अपनी गहरी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित विद्यार्थियों ने 2026 के अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित ओलंपियाड में देश के इतिहास का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। यह सफलता भारतीय युवाओं की अद्वितीय क्षमताओं का प्रमाण है और दशकों से सृजित राष्ट्रीय इकोसिस्टम की शक्ति को दर्शाता है, जो देश के प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान, मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए समर्पित है। ओलंपियाड टीमों की इस अद्वितीय सफलता से स्पष्ट होता है कि भारत की युवा शक्ति और प्रतिभाशाली छात्रों की वैश्विक मंच पर उनकी पूरी क्षमता को पहचान दिलाने के लिए लगातार निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2026 का ओलंपियाड सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के प्रदर्शन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ। चार ओलंपियाड में भारतीय दल ने 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते, जिनमें भौतिकी और रसायन विज्ञान में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके अलावा, जीव विज्ञान और गणित में भी भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विश्व के उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए, भारतीय छात्रों ने असाधारण वैज्ञानिक क्षमता, दृढ़ता एवं नवाचार का प्रदर्शन किया। इससे देश को अपार गौरव प्राप्त हुआ और विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान मिली।

परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने छात्रों की असाधारण उपलब्धियों पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारतीय छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव का विषय है और भारत की वैज्ञानिक भावना का उत्सव है। ये उपलब्धियां छात्रों के समर्पण, मार्गदर्शकों और शिक्षकों के अमूल्य मार्गदर्शन और दशकों से अथक परिश्रम से निर्मित संस्थागत व्यवस्था की मजबूती को दर्शाती हैं।

इस सफलता का मूल आधार होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (एचबीसीएसई) है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सहायता प्राप्त संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) का एक राष्ट्रीय केंद्र है। भारत के विज्ञान और गणित ओलंपियाड कार्यक्रमों के राष्ट्रीय नोडल केंद्र के रूप में, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र प्रतिभा की पहचान, मार्गदर्शन, उन्नत प्रशिक्षण और परामर्श की एक कठोर, बहु-स्तरीय प्रक्रिया संचालित करता है, जिससे देश के सबसे प्रतिभाशाली प्री-यूनिवर्सिटी स्तर के छात्रों को उच्चतम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के निरंतर संस्थागत समर्थन और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से यह कार्यक्रम विश्व के सबसे सम्मानित ओलंपियाड प्रणालियों में से एक के रूप में विकसित हुआ है।भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में परमाणु ऊर्जा विभाग के निरंतर समर्थन की सराहना करते हुए, एचबीसीएसई के केंद्र निदेशक प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य ने कहा कि वे इस विभाग के बहुमूल्य समर्थन और देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को विकसित करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए अत्यंत आभारी हैं। हमारे छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारी अगली पीढ़ी के युवा विद्वानों की पहचान करने, उनका पोषण करने और उन्हें प्रेरित करने के मिशन को सिद्ध करता है, साथ ही पूरे देश में विज्ञान और गणित के प्रति उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331
हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia